Ban on import of Indian Carpets

*98. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there are moves afoot in the U.S. to ban import of Indian carpets;

(b) if so, on what grounds; and

(c) the reaction of Indian Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULI RAMAIAH): (a) and (b) According to information available an amendment has recently been enacted under US Government's Treasury, Postal Services and General Appropriation Act, 1998 which reads as follows:

"Section 633. None of the funds made available in this Act for the United States Custom Service may be used to allow the importation into the United States of any goods, ware, article or merchandise mined, produced or manufactured by forced or indentured child labour, as determined pursuant to section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1307)."

There is a possibility that this amendment may have adverse impact on carpet exports from India.

In addition, some other bills have also been introduced recently in the U.S. Senate/Congress but according to information available these bills have yet not been passed.

The apparent reasons for enacting these legislations are their objective to inform an empower consumers in U.S. regarding goods made with abusive and exploitative child labour and to prohibit the import of articles produced or manufactured with bonded or indentured child labour.

(c) The steps being taken by the Government to counter the adverse impact of the legislation on carpet exports from the country include: examination of U.S. legislation and its implication in term of Indian Law; intensifying efforts for mobilizing support against trade restriction measures for reasons relating to labour standards considering raising the issue formally and informally at W.T.O; taking up the issue at diplomatic level with U.S. Government; inter-action with leading U.S. importers of Indian carpets; sending of delegation to U.S. by Carpet Export Promotion Council; publicity campaign; adoption of voluntary code of conduct by the carpet trade.

उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क का अपवंचन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध बकाया राशि

*99. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा-शुल्क का अपवंचन करने वाली कम्पनियों के खिलाफ उनकी ओर बकाया राशियों पर उपचित ब्याज की वसूली करने की कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार का निर्णय लेने में जानबूझकर विलम्ब कर रही है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (च) सरकार ने उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का बकाया राशियों पर ब्याज लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए है। सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों पर ब्याज तब संदेय हो जाता है जब कोई व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उप-धारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 क (2) के अंतर्गत निर्धारित किया जाने वाला प्रभार्य शुल्क अदा नहीं कर पाता है तथा 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाने वाला ब्याज उस तारीख से संदेय हो जाता है जिस तारीख से शुल्क भुगतान हेतु देय होता है। अपवंचित शुल्क पर ब्याज की अदायगी संबंधी उपबन्ध को वित्त अधिनियम 1996 द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में इसलिए शामिल किया गया है ताकि निर्धारितियों और आयातकों द्वारा